www.sanjanabharati.com | दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित | facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बेजा... | 3 एक देश, एक चुनाव-समय की आवश्यकता: अशोक | 4 निर्मम घटना के विरोध में इनेलो पार्टी 10 जून...

वर्ष: 9 | अंक: 223 | दिल्ली, शनिवार, 7 जून 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन प्रयत्न अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया- ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय संचार एवं उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय केशव कुंज में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित पुस्तक "हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी" का विमोचन किया। इस किताब को प्रो. ओमप्रकाश सिंह एवं डॉ. देवेंद्र भारद्वाज द्वारा संपादित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि कुछ लोग इतिहास के पन्नों में उलझे रहते हैं और कुछ लोग शिवाजी महाराज की तरह इतिहास बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब 14 वर्ष के शिवाजी ने भगवान शिव के सामने एक प्रण लिया कि किस तरह एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाए जिसमें गरीब, मजदूर किसान और हर वर्ग की भागीदारी हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह बताया कि किस तरह स्वराज्य के आधार पर अपने राज्य को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने आम लोगों और अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ी और आक्रमणकारी मुगलों को धूल चटा दी।

2027 में पीडीए सरकार में ही सही ढंग से होगी जाति जनगणना-अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि जाति जनगणना 2027 में पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार के तहत ही ठीक से की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि 2027 में पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) सरकार में जाति जनगणना होगी। तभी जनगणना सही तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने दावा किया कि आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक अधूरा संग्रहालय है, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार न केवल पूरा कराएगी, बल्कि लखनऊ में शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित करेगी। अखिलेश यादव ने कहा, "छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व के सम्मान में...आगरा में एक अधूरा संग्रहालय है, जिसके वास्तुकार विश्व प्रसिद्ध हैं...हम समाजवादी न केवल उनके नाम पर संग्रहालय बनाएंगे, बल्कि लखनऊ रिवरफ्रंट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित करेंगे; उनका सिंहासन सोने का बना होगा।

वक्फ संपत्तियों की अब एक क्लिक में मिलेगी जानकारी, किरेन रिजिजू

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया और कहा कि यह वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को डिजिटल बनाएगा और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज, वक्फ संशोधन अधिनियम की पहली कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह उम्मीद पोर्टल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को डिजिटल करेगा ताकि कोई इसका दुरुपयोग या बाईपास न कर सके। यह पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से काम करेगा। दक्षता और सशक्तिकरण इस अधिनियम का सबसे बड़ा उद्देश्य है... यह सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन विशेष रूप से गरीब मुस्लिम बच्चों, महिलाओं, अनाथों और विधवाओं के लिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया

संजना भारती/पीआईबी

जम्मू-कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के कटरा में 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। वीर जोरावर सिंह की भूमि को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम भारत की एकता और दृढ़ संकल्प का भव्य उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से कश्मीर घाटी अब भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जुड़ गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने हमेशा गहरी श्रद्धा के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हुए मां भारती का आह्वान किया है, आज यह हमारे रेल नेटवर्क में भी एक वास्तविकता बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लाइन परियोजना केवल एक नाम नहीं है, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर की नई ताकत और भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक है। क्षेत्र में रेल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, उन्होंने चिनाब और अंजी रेल पुलों का उद्घाटन किया और जम्मू-कश्मीर के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त, श्री मोदी ने जम्मू में एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। उन्होंने कहा कि 46,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर में विकास को गति देंगी, जिससे प्रगति और समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने विकास और परिवर्तन के इस नए युग के लिए लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दीं।

श्री मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पीढ़ियों ने रेलवे कनेक्टिविटी का सपना लंबे समय से देखा था, आज यह सपना सच हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हाल ही में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सातवीं या आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के रूप में

भी श्री अब्दुल्ला इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस आकांक्षा की पूर्ति जम्मू-कश्मीर के लाखों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो बेहतर कनेक्टिविटी और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

उन्होंने कहा कि यह उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि इस महत्वाकांक्षी रेलवे परियोजना ने उनके कार्यकाल के दौरान गति पकड़ी और अब सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस परियोजना में कई चुनौतियां थीं, जैसे कि कठिन भूभाग, खराब मौसम की स्थिति और पहाड़ों में गिरती चट्टानें, जिससे यह परियोजना बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गई थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा चुनौतियों का सामना करने और दृढ़ संकल्प के साथ उन पर विजय पाने का विकल्प चुना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चल रही सभी मौसमों में कार्यशील रहने वाली कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इस प्रतिबद्धता का उदाहरण हैं। उन्होंने हाल ही में खोली गई सोनमर्ग सुरंग और चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज पर यात्रा करने के अपने अनुभव को उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने भारत के इंजीनियरों और श्रमिकों की इंजीनियरिंग प्रतिभा और अटूट समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज भारत की महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जहां लोग एफिल टॉवर देखने के लिए पेरिस जाते हैं, वहीं चिनाब ब्रिज की ऊंचाई उससे भी अधिक है, जिससे यह न केवल एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्धि बन गया है, बल्कि एक उभरता हुआ पर्यटक आकर्षण भी बन गया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री ने अंजी ब्रिज को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया, जो भारत का पहला केबल-समर्थित रेलवे ब्रिज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये संरचनाएं केवल स्टील और कंक्रीट से बनी नहीं हैं, बल्कि भारत की शक्ति के जीवंत प्रतीक हैं, जो पीर पंजाल पहाड़ों के ऊबड़-खाबड़ ऊंचे स्थान पर खड़े हैं। श्री मोदी कहा कि ये उपलब्धियां एक विकसित राष्ट्र के लिए भारत के विजान का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो साबित करती हैं कि भारत की प्रगति का सपना जितना बड़ा है, उतना ही उसका लचीलापन, क्षमता और दृढ़ संकल्प भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शुद्ध इरादे और अथक

जम्मू और कश्मीर भारत का मुकुट रत्न है: प्रधानमंत्री

समर्पण भारत के रूपांतरण के पीछे की प्रेरक शक्तियां हैं।

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज दोनों ही जम्मू-कश्मीर में समृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा, "ये ऐतिहासिक परियोजनाएं न केवल पर्यटन को बढ़ावा देंगी बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेंगी, जिससे व्यवसायों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे"। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू और कश्मीर के बीच बेहतर रेल संपर्क स्थानीय उद्यमियों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि कश्मीर के सेब अब कम लागत पर देशभर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचेंगे, जिससे व्यापार में अधिक कुशलता आएगी। इसके अतिरिक्त, सूखे मेवे और कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना शॉल और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प अब आसानी से देश के हर कोने में पहुंचाए जा सकेंगे, जिससे क्षेत्र के कारीगरों और उद्योग को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बेहतर संपर्क जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आवाजाही और अधिक सुविधाजनक बनाएगा, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों में आवागमन सुगम हो सकेगा।

श्री मोदी ने संगलदान के एक विद्यार्थी की मार्मिक टिप्पणी साझा की, जिसने कहा कि अब तक केवल उन लोगों ने ही वास्तविक जीवन में रेलगाड़ी देखी थी जिन्होंने गांव से बाहर कदम रखा था। अधिकांश ग्रामीणों ने केवल वीडियो में ही रेलगाड़ियां देखी थीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि शीघ्र ही उनकी आंखों के सामने से एक वास्तविक रेलगाड़ी भी गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि कई लोगों ने अब रेलगाड़ियों की समय-सारिणी को भी याद करना शुरू कर दिया है और वे नई कनेक्टिविटी को लेकर काफी उत्साहित हैं।

दिव्यांगों के लिए राज्य में विकसित हो रही हैं कई सुविधाएं: रविन्द्र इन्द्राज

नरेला में दिव्यांगों के लिए तैयार हो रहे भवन का मंत्री ने किया निरीक्षण

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, चुनाव और सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने शुक्रवार को नरेला में मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए तैयार हो रहे भवन का पीडब्ल्यूडी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि कैम्पस दिव्यांगों के लिए आवश्यक सुविधाओं के अनुरूप तैयार हो रहा है। इसके तैयार होने पर रोहिणी के आशा होम्स जैसे जिन शेल्टर होम्स में क्षमता से अधिक दिव्यांग रह रहे हैं, उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जा सकेगा।

नरेला में नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल बिल्डिंग, प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र परिसर में दिव्यांगों के लिए तैयार हो रहे भवन में 220 दिव्यांगों के रहने की सुविधा होगी। यह सुविधा तीन महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। समाज कल्याण मंत्री ने निर्देश दिए कि कैम्पस डिसएबल्ड फ्रेंडली हो, कार्य गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा करें, परिसर के बाहर अतिक्रमण न हो और एंबुलेन्स की आवाजाही में कोई समस्या न आए।

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि राज्य में दिव्यांगों के लिए कई सुविधाएं विकसित हो रही हैं। मामूरपुर और दल्लूपुरा में भवन तैयार होने के बाद दिव्यांगों के लिए सुविधा, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकल्प बढ़ेंगे।

'पलवल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉर्डन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स'

'पलवल शहर के बाहर बनेगी नई अनाज मंडी'

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवलवासियों को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देते हुए विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉर्डन स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बनाया जाएगा। साथ ही, 55 लाख रुपये की लागत से पलवल में इनडोर स्टेडियम को साउंडप्रूफ बनाया जाएगा। इसके अलावा, सेक्टर- 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति इत्यादि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए उपरोक्त घोषणाएं की। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपये की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 24 करोड़ 71 लाख रुपये लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में 152 किलोमीटर की 75 सड़कें, जो अभी गारंटी पीरियड में हैं, संबंधित एजेंसियों के माध्यम से इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। साथ ही, 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की मरम्मत के लिए 37 करोड़ 57 लाख रुपये तथा 54.5 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों के नवीनीकरण के लिए 40 करोड़ 18 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी की रिमॉडलिंग के लिए 50 लाख रुपये तथा 5 गांवों में वीआर ब्रिज के लिए 13 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। जमीन उपलब्ध होने पर मुस्तफाबाद में 66 केवी और पलवल में लाइन पार क्षेत्र में 220 केवी का सब स्टेशन बनाया जाएगा। पलवल शहर में भूमि उपलब्ध होने पर विभागीय मानदंडों के अनुरूप दो नए स्कूल खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल शहर से बाहर भूमि उपलब्ध होने पर नई अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। वार्ड नंबर 1 से 10 में कॉलोनियों में कच्ची गलियों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांवों में सामुदायिक केंद्रों के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा। बडौली को सब तहसील बनाने के लिए इस संबंध में गठित कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा, अन्य मांगों की फिजिबिलिटी चैक करवाकर, उन्हें भी पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगरा नहर की पटरी पर सड़क के विस्तार के फिजिबिलिटी चेक करवाकर इसे बनाने का कार्य किया जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपये की घोषणा की।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों में हर भारतवासी ने एक ऐसे भारत का उदय देखा है, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डटकर सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छाशक्ति और 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूलमंत्र ने देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रधान सेवक का पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरे संसार में 11वें स्थान पर थी, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में विकास की गति धीमी थी और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता था, न ही उनको योजनाओं का लाभ मिलता था। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार ने हरियाणा में दोगुनी गति से विकास कार्य किए हैं। 10 सालों से अधिक समय के कार्यकाल में पलवल विधानसभा क्षेत्र में 1270 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि 2014 से पहले हरियाणा के 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, जबकि आज वर्तमान सरकार द्वारा 36 लाख से अधिक बुजुर्गों को 3 हजार रुपये महीना सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में फसल खराबे पर किसानों को केवल 1155 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया, जबकि हमारी सरकार ने 10 सालों में 15,145 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया। कांग्रेस के समय में गरीबों को बीमारियों के इलाज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जबकि आज आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों का इलाज हो रहा है। इसके तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को 2 हजार 767 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज प्रदान किया गया है।

धान के सीजन के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा की गई 1000 मेगावाट बिजली की मांग को जल्द पूरा करने की मांग

बिजली मंत्री ने आर.डी.एस.एस. योजना का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के बिजली मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब राज्य में 800-800 मेगावाट के 3 और बिजली उत्पादन यूनिट स्थापित करने की मांग को केंद्रीय बिजली मंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आज यहां भारत सरकार के बिजली विभाग द्वारा उत्तर भारत के बिजली मंत्रियों के लिए रखी गई कॉन्फ्रेंस में पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स हरभजन सिंह ई टी ओ ने यह मुद्दा उठाया था।

इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता भारत सरकार के बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली सरकार के बिजली मंत्रियों और अधिकारियों ने शिरकत की।

बिजली मंत्री ने रोपड़ थर्मल प्लांट की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि पंजाब के पास अपनी कोयले की खान है, परंतु केंद्र सरकार द्वारा कोयले की ढुलाई 1000 किलोमीटर से अधिक न करने की शर्त के कारण इन थर्मल प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने में आ रही दिक्कत का मुद्दा उठाया। इस मांग को स्वीकार करते हुए केंद्रीय बिजली मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी कि कोयला ले जाने की सीमा को 1500 किलोमीटर से बढ़ा दिया जाए और पंजाब के रोपड़ में 800-800 मेगावाट के दो और बिजली उत्पादन प्लांट को स्थापित करने की अनुमति दे दी जाए। इसके साथ ही 800 मेगावाट का एक नया यूनिट पंजाब में स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय बिजली मंत्री की इस मंजूरी से पंजाब में 2400 मेगावाट के थर्मल प्लांट स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के दिए गए लक्ष्य के बारे में बोलते हुए हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब में आवश्यक भूमि की कीमत ज्यादा होने के कारण इस दिशा में लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत आ रही है, परंतु पंजाब सरकार किसी पड़ोसी राज्य में यह सौर प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रयासरत है, जहां से बिजली की आपूर्ति भी आसानी से पंजाब को हो जाए।

इस मौके पर बिजली से संबंधित पंजाब के पक्ष को मजबूती से रखते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने धान के सीजन के मद्देनजर पंजाब सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मांगी गई 1000 मेगावाट बिजली को जल्द पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि देश के अन्न भंडार को सुरक्षित करने के लिए हमेशा पंजाब द्वारा बढ़-चढ़कर योगदान दिया गया है, इसलिए धान के सीजन को ध्यान में रखते हुए पंजाब की इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर बिजली मिल सके और वे धान को आवश्यकतानुसार पानी दे सकें। वर्तमान समय में पंजाब राज्य को केंद्रीय पूल से 275 मेगावाट बिजली मिल रही है।

उन्होंने कहा कि बीबीएमबी जालंधर में पहले से लगे हुए 100 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाकर 160 एमवीए करने संबंधी सभी आवश्यक स्वीकृतियां हासिल की जा चुकी हैं और इस कार्य के लिए खर्च भी पंजाब सरकार द्वारा किया जाना है, परंतु फिर भी यह मामला अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में लंबित कार्यवाही को जल्द पूरा किया जाए ताकि बीबीएमबी जालंधर की इकाई को सही तरीके से चलाया जा सके।

बिजली मंत्री ने इस मौके पर केंद्र सरकार की आर.डी.एस.एस. योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस योजना के तहत पंजाब राज्य के बिजली आपूर्ति ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 60-40 के अनुपात में 3600 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 60 प्रतिशत हिस्सा देना था, परंतु अब इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने के कारण और केंद्रीय अनुदान निश्चित होने के कारण अनुदान का प्रतिशत 60 घटकर 40 रह गया है, जिसके कारण पंजाब राज्य को लगभग 300 करोड़ का घाटा होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस स्थिति के मद्देनजर नए दरों पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाए।

बिजली मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार पंजाब राज्य में जल्द ही साइबर सुरक्षा ऑडिट करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्यवासियों को बेहतरीन बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सम्पादकीय

जल है तो कल है

जल है तो कल है कि चुनौती के बीच राजस्थान की भजन लाल सरकार द्वारा समूचे प्रदेश में मानसून से पूर्व 5 जून से 20 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण–जन अभियान इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दादरा–नगर हवेली और दमन दीव देष के ऐसे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश है जहां भूजल की निकासी भूजल के पुनर्भरण से कहीं अधिक हो रही है। अगर राजस्थान ही की बात करें और वह भी शुद्ध पेयजल की बात की जाए तो पीने योग्य पानी और उसकी उपलब्धता में 30 फीसदी का अंतर है। 30 प्रतिशत का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है ऐसे में इसे भलीभांति समझा जा सकता है कि राज्य सरकार को नागरिकों के लिए पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता बनाये रखने की चुनौती से कैसे दो–चार होना पड़ता होगा। वास्तव में यह गंभीर समस्या है। समूचे विश्व में पानी की उपलब्धता का संकट है। यदि हम भारत की ही बात करें तो 1950 में जहां प्रतिव्यक्ति सालाना 5200 घनमीटर पानी की उपलब्धता थी वह 2024 आते आते 1401 घनमीटर रह गई है और यदि विशेषज्ञों की माने तो 2050 तक यह उपलब्धता 1191 घनमीटर ही रह जाने की संभावना हो गई है। यही कारण है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों कहा कि हमें पानी के उपयोग के संदर्भ में कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रित करने की नीति पर चलना होगा। देश में जल के पुनर्भरण में लगातार कमी आ रही है। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में आज भारत 182 वें स्थान पर आ गया है। भूजल की उपलब्धता को देखा जाए तो 1950 से 2024 के दौरान 73 प्रतिशत की कमी आ गई है। दिल्ली, चैन्नई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई सहित देश के अनेक छोटे बड़े शहर पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। विश्वव्यापी जल संकट को देखते हुए राजस्थान की भजन लाल सरकार की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। दरअसल देश में उपलब्ध भूजल का 87 प्रतिशत उपयोग खेती किसानी में होता है तो 11.7 प्रतिशत उपयोग घरेलू कार्यों और लगभग 2 प्रतिशत उपयोग ही औद्योगिक क्षेत्र में होता है। संकट का बड़ा कारण परंपरागत जल संग्रहण स्रोतों का नष्ट होना, उनमें अवरोध होना, बढ़ती आबादी और शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व बढ़ने के साथ ही अत्यधिक पानी की आवश्यकता वाली उपज को बढ़ावा देने से जल दोहन अधिक होने लगा है। सीवेज के कारण पानी का अत्यधिक उपयोग, बरसाती जल का प्रोपर संग्रहण नहीं होना, जंगलों का कंक्रिट के जंगलों में बदलना और पानी के अन्य कार्यों में भी अत्यधिक उपयोग से पानी का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अनियमित बरसात और बरसाती चक्र में बदलाव को भी एक कारण माना जा सकता है। आज जितने पानी के पीने के लिए आवश्यकता होती है उससे कई गुणा अधिक पानी फ्लस करने, वाहनों की धुलाई, पौधों के रखरखाव व अन्य कार्यों में होने लगा है। सीमेंट, लोहा, जस्ता और अब एमसेंड आदि उद्योगों के लिए भी अधिक पानी की आवश्यकता होने लगी है। एक समय था जब सावन भादों में बरसात की झड़ी लगती थी और कई दिनों तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते थे तो उस झड़ी का पानी सीधे जमीन में जाता था और वह प्राकृतिक वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होता था। सड़कों के साथ साथ ढ़लान क्षेत्र होता था और वहां एकत्रित पानी क्षेत्र में जल स्तर बढ़ाने के साथ ही पशुओं के पीने के काम भी आ जाता था। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में टांके आदि परंपरागत जल संग्रहण के साधन होते थे आज हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गिरते भूजल स्तर और जल संग्रहण को लेकर सरकार गंभीर ना हो। बल्कि कहना तो यह होगा कि सरकार अत्यधिक गंभीर होने के बावजूद जो परिणाम आने चाहिए वह प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसका एक प्रमुख कारण दूरगामी सोच के साथ नीति और क्रियान्वयन का ना होना भी है। सरकार द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सरकार स्तर पर बड़े स्तर पर बनाने और निजी मल्टी स्टोरिज व सरकार गैरसरकारी संस्थानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने पर जोर और बनाये जाने के बावजूद उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल इसलिए उठते रहते हैं कि ना तो रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है और ना ही पानी के बहाव का पूरा ध्यान देने के कारण यह अपने उद्देश्यों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसा नहीं है कि इन हालातों से सरकार अनजान हो यहीं कारण है कि राजस्थान की भजन लाल सरकार ने मानसून के ठीक पहले पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 20 जून तक समूचे प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण–जन अभियान संचालित कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है और स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका की मुहिम पर रामगढ़ में श्रमदान में हिस्सा लेकर आमजन को संदेश दिया है। राज्य सरकार द्वारा समूचे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के दौरान जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल प्रदूषण में कमी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता, भूजल पुनर्भरण, व्यवहार परिवर्तन से बेहतर जल उपयोग और व्यापक स्तर पर पौधारोपण के हरियालो राजस्थान की तैयारी आरंभ की है। रामगढ़ राजस्थान की राजधानी जयपुर की किसी जमाने में पेयजल की उपलब्धता के लिए जीवन रेखा माना जाता था और 1982 के एशियाड़ की नौकायन प्रतियोगिता के बाद इसके बहाव क्षेत्र में अतिक्रमणों का जो ग्रहण लगा वह इसे सूखे मैदान में बदल कर रख दिया है।

जयंती

ख़्वाजा अहमद अब्बास

जन्मः 7 जून 1914, मृत्युः 1 जून 1987) प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक थे। वे उन कुछ गिने चुने लेखकों में से एक थे, जिन्होंने मुहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 'अलीगढ़ ओपिनियन' शुरू किया। 'बॉम्बे क्रॉनिकल' में ये लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फि ल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ 'द लास्ट पेज' सबसे लंबा चलने वाले स्तंभों में गिना जाता है। यह 1941 से 1986 तक चला। अब्बास इप्टा के संस्थापक सदस्य थे।

पुण्यतिथि

नटराज रामकृष्ण

जन्म–21 मार्च, 1923; मृत्यु–7 जून, 2011) भारत के एक नृत्य गुरु थे। वे आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे थे। वह एक विद्वान और संगीतज्ञ भी थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश और दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें से कई को अत्यधिक सम्मानित किया गया। नृत्य की कला में नटराज रामकृष्ण के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

कल मिलेंगे

अंकल–फ्री टाइम में क्या करते हो?
Boy–जी फोन चार्ज करता हूं.
अंकल–और फ्री कब होते हो?
Boy–जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल के लिए दोषी कौन?

-कमलेश पांडे

देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने अपने लहजे में न्यायपालिका की बड़ाई और शिकायत दोनों करते हुए परोक्ष रूप से न्यायाधीशों, नौकरशाहों व राजनेताओं के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करते हुए उन्हें कतिपय नसीहतें भी दी हैं, जिन्हें समझे जाने और उसके दृष्टिगत सर्वश्रेष्ठ समाधान निकाले जाने की जरूरत है

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए जजों का स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए कतिपय जजों ने जो कुछ कारनामें किए हैं, उसके दृष्टिगत न्यायपालिका में मूलभूत बदलाव नहीं करना जनतंत्र के लिए भी अहितकर साबित हो रहा है। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल के लिए आखिर में दोषी कौन है? और उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने, करवाने में न्यायिक प्रशासन या फिर कार्यपालक प्रशासन के हाथपांव क्यों फूलने लगते हैं? यदि पुरानी बातें छोड़ भी दें तो जस्टिस जे एस वर्मा के खिलाफ जितनी मंथर गति से कार्रवाई चल रही है, वह पूरी संवैधानिक व्यवस्था के लिए गम्भीर चिंता की बात है। इससे भ्रष्टाचार के संलिप्त लोगों को बढ़ावा मिलेगा।

सुलगता सवाल है कि किसी भी मामले में जितनी ततपरता पूर्वक आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उतनी ही ततपरतापूर्वक कार्रवाई किसी खास आदमी के खिलाफ आखिर क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या चोर-चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहां भी चरितार्थ होती है? आखिर हमारी संसद इन विषयों पर स्पष्ट और पारदर्शी कानून क्यों नहीं बनाती है? हमारे देश में संसद सर्वोच्च है या सुप्रीम कोर्ट, यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह चर्चा समीचीन है कि विधायिका या न्यायपालिका में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों के खिलाफ आम आदमी की तरह नहीं बल्कि खास आदमी की तरह विलंबित कार्रवाई आखिर क्यों होनी चाहिए?

चूंकि विधायिका और न्यायपालिका दोनों ने अपनी सर्वोच्च स्थिति का दुरूपयोग किया है, इसलिए लोकहित या व्यवस्था हित वाले रेयर ऑफ द रेयररेस्ट मामलों में विद्वत परिषद या जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने की वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने मुख्य न्यायाधीश ग्रेट ब्रिटेन में वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में 'न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के' विषय पर जो बातें कही हैं, उनपर गौर फरमाना हर प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए लाजिमी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि ज्यूडिशियरी में करप्शन और मिसकण्डक्ट से न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्यूडिशियरी को केवल न्याय नहीं करना है, बल्कि उसे एक संस्थान के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो सत्ता से सच कहने की क्षमता रखता है।

कहना न होगा कि जहां एक ओर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ों को खोखली करने में भी न्यायपालिका की प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस देश में चल रहे विभिन्न न्यायिक घटनाक्रमों का सार-सत्य कुछ ऐसा ही है, जो चिंताजनक बात है।

देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने अपने लहजे में न्यायपालिका की बड़ाई और शिकायत दोनों करते हुए परोक्ष रूप से न्यायाधीशों, नौकरशाहों व राजनेताओं के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करते हुए उन्हें कतिपय नसीहतें भी दी हैं, जिन्हें समझे जाने और उसके दृष्टिगत सर्वश्रेष्ठ समाधान निकाले जाने की जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार ने दो बार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया क्योंकि उस समय अंतिम निर्णय सरकार का था। यही वजह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया और कहा कि इससे जजों की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है।

दरअसल, उक्त गोलमेज सम्मेलन में जस्टिस विक्रम नाथ, इंग्लैंड और वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस बैरोनेस कैर और यूके के सुप्रीम कोर्ट के जज जॉर्ज लेगट की मौजूदगी में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि, 'भारत में, न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच विवाद का एक मुख्य मुद्दा यह रहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता किसकी है? उन्होंने कहा कि 1993 तक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता था। यही वजह है कि उक्त अवधि के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका ने दो बार जजों के फैसले को अनदेखा किया, जो स्थापित परंपरा के विरुद्ध था।'

उल्लेखनीय है कि सीजेआई पद के लिए जिन दो जजों को दरकिनार किया गया है, वे हैं जस्टिस सैयद जाफर इमाम और जस्टिस हंस राज खन्ना। जहां जस्टिस इमाम को 1964 में शीर्ष पद नहीं सौंपा जा सका था क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने जस्टिस पीबी गजेंद्रगढ़कर को यह पद सौंपा था। वहीं, न्यायमूर्ति खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब एडीएम जबलपुर बनाम शिव कांत शुक्ला मामले में उनके असहमति वाले फैसले के कुछ महीनों बाद ही उन्हें चीफ जस्टिस का पद खोना पड़ा था। क्योंकि उस मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यही बात इंदिरा गांधी सरकार को नागवार गुजरी थी।

सीजेआई के मुताबिक, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 और 1998 के अपने फैसलों में जजों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की और स्थापित किया कि भारत के चीफ जस्टिस, चार सीनियर जजों के साथ मिलकर एक कॉलेजियम का गठन करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था। क्योंकि इस अधिनियम ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता देकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए।

वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा सरकारी पद ग्रहण करना, या त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना नैतिक चिंताएं पैदा करता है। भारत में जजों के लिए एक निश्चित रिटायरमेंट उम्र होती है। यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति लेता है, या चुनाव लड़ने के लिए पीठ से इस्तीफा देता है, तो यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। क्योंकि तब लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अक्सर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार होती आई है। इस बीच सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने अंग्रेजों की धरती से जजों की नियुक्ति को लेकर जो अहम टिप्पणी की है, उसके न्यायिक मायने तो स्पष्ट हैं, लेकिन न्यायिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाये हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। हालांकि चीफ जस्टिस बीआर गवई ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस की गलतियों को जो याद दिलाया है, वह शायद भाजपा को खुश करने की एक सार्थक पहल हो सकती है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने जजों को भी नसीहत देते हुए कहा है कि जजों को हर हाल में स्वतंत्र रहना चाहिए।

इसलिए बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई न्यायिक जांच पुलिस कैडर का गठन करने का आदेश दें, जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर पेशेवर तौर पर नजर रखेगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार करके खास जेल में डालकर विधिक कार्रवाई शुरू करेगी। आप मानें या न मानें, निचली अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश व अधिवक्ताओं की मिलीभगत से संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिरी है व विश्वसनीयता कम हुई है। इसे रोकने में कार्यपालिका व विधायिका की दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि ये खुद ही महाभ्रष्ट हैं! अपवाद हरेक जगह पर हैं, लेकिन अल्पमत में, बेहद कम।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

बेंगलुरु में व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे का बेनकाब होना

-ललित गर्ग

भारत में भीड़ से जुड़े हादसे अनेक आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ भीड़ प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटावन हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी

बढ़ते तापमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की शानदार जीत के बाद आयोज्य जश्न के मातम, हाहाकार एवं दर्दनाक मंजर ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल ही नहीं खोली बल्कि सत्ता एवं खेल व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है। आरसीबी विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भगदड़ में लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई, यह राज्य प्रायोजित एवं प्रोत्साहित हत्या है। पुलिस का बंदोबस्त कहां था? चीख, पुकार और दर्द और क्रिकेट सितारों को देखने की दीवानगी एक ऐसा दर्दनाक एवं खौफनाक वाकया है जो सुदीर्घ काल तक पीड़ित और परेशान करेगा। प्रशासन की लापरवाही, अत्यधिक भीड़, निकासी मार्गों की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में सामने आई ऐसी घटनाओं की कड़ी का नया खौफनाक मामला है, जहाँ भीड़ नियंत्रण में चूक एवं प्रशासन एवं सत्ता का जनता के प्रति उदासीनता का गंभीर परिणाम एवं त्रासदी का ज्वलंत उदाहरण है।

क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें संस्करण में आईपीएल खिताब जीत लिया। इस कामयाबी से आईपीएल से विदाई ले रहे विराट कोहली के प्रति जन-उत्साह उमड़ा। लेकिन इस जीत के जश्न की चमक में प्रशंसकों की चीखें एवं आहें का होना और उसे खिलाडियों एवं राजनेताओं द्वारा नजरअंदाज करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें हो जाने के बावजूद जश्न जारी रहना, दुखद एवं शर्मनाक है। प्रशंसकों की अहमियत को कमतर आंकने के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने न केवल राजनेताओं को बल्कि खिलाड़ियों को भी दागी किया है। घटना ने एक बार फिर हमारे अवैज्ञानिक व लाठी भांजने वाले भीड़ प्रबंधन की ही पोल खोली है। इस जीत के जश्न में हिस्सा लेने आई भीड़ का एक लाख तक होने का अनुमान था। लेकिन लंबे अंतराल के बाद मिली जीत ने लोगों के उत्साह को इस स्तर तक पहुंचा दिया कि स्टेडियम के आसपास तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मौत की खबरें मिलने के बावजूद खिलाडियों के साथ जश्न मनाने में जुटा रहना उनकी प्रचार भूख का भौंडा उदाहरण है। जब मौत के बाद वहां पसरा मातम देखकर सब स्तब्ध थे तो सिद्धारमैया क्यों अपने पद की गरिमा एवं जिम्मेदारी को धूमिल कर रहे थे? सोचिए लोगों की मौत के बाद अगर एक मिनट भी जश्न मना, तालियां बजीं, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का मातम में बदलने का नेतृत्व करेगी तो आम लोगों का कांप उठना स्वाभाविक है।

बहरहाल, आईपीएल का आयोजन लगातार नई ऊंचाइयों को छूता हुआ व्यावसायिक क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने में जरूर सफल रहा है। फटाफट क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में भारत के दो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों विराट कोहली व एमएस धोनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अंततः विराट कोहली का आईपीएल खिताब जीतने का लंबा इंतजार इस जीत के साथ खत्म हुआ। लेकिन धोनी पांच बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग को जीत का खिताब दिलाने से चूक गए। एक तरह से आईपीएल क्रिकेट से कोहली की यह शानदार विदाई साबित हुई। वे इस गरिमामय विदाई के हकदार भी थे। उनके करोड़ों प्रशंसकों की कतारे देख कर राजनेता भी उनकी साथ मंच सांझा करने को उत्सुक दिखे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, अन्य मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी भी इसी फिराक में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जश्न मनाते रहे और आमजनता अव्यवस्थाओं के कारण मौत में समाती रही। यह ऐसी दुखद घटना है जो अपनी निर्दयता एवं क्रूरता के लिये लम्बे समय तक कौंधती रहेगी। सिद्धारमैया के इस घटना की तुलना प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे के करना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रही है।

भारत में भीड़ से जुड़े हादसे अनेक आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ भीड़ प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटावन हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में मक्का में हज के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के रत्नागढ़ मंदिर में ढाँचागत कमियों से प्रेरित भगदड़ के कारण 115 लोगों की मौत हो गई थी। हालही में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन एवं प्रयागराज में हुए हादसे में भी अनेकों लोगों की जान गयी। आग, भूकंप, या आतंकी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियाँ में भी भीड़ प्रबंधन की पौल खुलती रही है। आखिर दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में हम भीड़ प्रबंधन को लेकर इतने उदासीन क्यों है? बड़े आयोजनों-भीड़ के आयोजनों में भीड़ बाधाओं को दूर करने के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जन जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अब नितान्त आवश्यक है।

रेलवे स्टेशन, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त जगह और रास्ते नहीं हैं। कुछ स्थानों पर निकास मार्ग सीमित हैं या अनुपयुक्त हैं, जो भगदड़ का खतरा बढ़ाते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित एवं दक्ष सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों, जैसे कि एआई आधारित निगरानी और ड्रोन कैमरे का उपयोग सीमित है। लोगों को आपातकालीन निकास मार्गों, भीड़ नियंत्रण नियमों, और सुरक्षा उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। गलत सूचना या अचानक दहशत से भीड़ अनियंत्रित हो सकती है और भगदड़ मच सकती है। भीड़ का व्यवहार कई बार अनियंत्रित हो जाता है, खासकर धार्मिक, खेल एवं सिनेमा आयोजनों में, जहां लोग भावनाओं में बहकर आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। कई बार आयोजनकताओं और पुलिस के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे सुरक्षा चूक हो सकती है। भीड़ प्रबंधन केवल विधि-व्यवस्था बनाए रखने का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों की संरचना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीतियों से गहनता से संबद्ध है। दुर्भाग्यवश, कई बार आयोजकों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते, जिससे जानमाल की हानि होती है। इस परिदृश्य में, बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की मौजूदा स्थिति, उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ, हालिया घटनाओं से मिले सबक और प्रभावी समाधानों की चर्चा करना बेहद प्रासंगिक होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में धार्मिक उत्सव, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में लाखों लोग जुटते हैं। ऐसे आयोजनों के लिये पुलिस, होम गार्ड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाता है। विश्व के विभिन्न विकसित देशों में भीड़ प्रबंधन के लिये अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जापान जैसे देशों में रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़ के प्रबंधन के लिये ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट सिस्टम स्थापित किये गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में स्टेडियमों, एयरपोर्ट्स एवं धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिये एआई आधारित कैमरे, आपातकालीन अलर्ट सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। हालाँकि भारत में बड़े आयोजनों के लिये प्रशासनिक तैयारियाँ की जाती हैं, फिर भी समय-समय पर कई कमियाँ उजागर होती रही हैं। लेकिन आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम के जश्न के दौरान खामियां ही खामियां देखने को मिली। ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन कोई आसान कार्य नहीं है। लाखों लोगों को नियंत्रित करने के लिये ठोस रणनीति, प्रशासनिक कौशल और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसका इस आयोजन में सर्वथा अभाव रहा। आखिर इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषी लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

एलन मस्क ने की ट्रंप पर महाभियोग लाने की मांग

(एजेन्सी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ एलन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाने की बात भी कही है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे तो आपने ट्रंप और मस्क की दोस्ती देखी थी। किस तरह से हर चुनाव प्रचार में मस्क हमेशा ट्रंप के साथ रहते थे और ट्रंप भी इस बात को मानते हैं कि दोनों के अबतक के संबंध बेहद ही अच्छे रहे हैं। लेकिन ट्रंप इस बात को भी दोहरा चुके हैं कि अब उनके संबंध शायद ही पहले जैसे रह सके। ऐसे वक्त में अब एलन मस्क की एक नई डिमांड सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनना चाहिए। इसके साथ ही ट्रंप पर महाभियोग की मांग भी की गई है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। सरकारी विभागों में उन्होंने कटौतियां की और कर्मचारियों की छटनी की। बेफिजूल खर्च पर लगाम लगाया गया और ये टारगेट एक साल में एक तिहाई खर्च को कम करने का था। डीओजीई के तहत वो अपना काम बखूबी कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो कैमेस्ट्री थी, जो बॉन्डिंग थी वो कई मंच से व कई मौकों पर तस्वीरों के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखी। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेता करीब आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी जीत का श्रेय एलन मस्क को ही एक्सपर्ट्स ने तब दिया था। उन्होंने ट्रंप का सिर्फ समर्थन ही नहीं किया बल्कि ट्रंप के प्रचार में लगभग सात करोड़ डॉलर खर्च भी किए। उन्हीं एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत के बाद सबसे बड़ा तोहफा डीओजीई चीफ बनाकर दिया। आपको याद होगा जब ट्रंप पर अटैक हुआ था। उसीवक्त एलन मस्क ने उनका साथ दिया था और फंडिग भी की थी। लगातार वो तारीफों के पुल बांधते रहे। यहां तक की टैरिफ की भी जब घोषणा की गई तो वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिकी टैक्स बिल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अब तक उनके करीबी रहे उद्योगपति एलन मस्क के बीच 'महासंग्राम' शुरू हो गया है। मामला इतना बिगड़ गया कि मस्क ने ट्रम्प को 'एहसान फरामोश' कह दिया।

तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी से पहले इस नाम से जानी जाती थी ये टेस्ट सीरीज

(एजेन्सी)।

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। ये टेस्ट सीरीज 20 जून से शुरू होगी और 4 अगस्त तक चलने वाली है। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो गई है। इस दौरे के लिए शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गी है वहीं अब इस ट्रॉफी को सचिनतेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के नाम पर किया जा रहा है। भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को तेंदुलकर एंडरसन सीरीज नाम दिया जाने वाला है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने साथ मिलकर ये फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी का अनावरण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किया जाएगा, जो कि 11 जून से होने वाली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा।

भारत- इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट सीरीज जब इंग्लैंड में आयोजित होती है, तब इसे पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। जब ये ट्रॉफी भारत में खेली जाती है तो इसे एंथनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता था। भारत-इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट सीरीज नए WTC साइकिल की शुरूआत करने वाली है। इसका पहला मैच हेडिंग्ले में खेला जाएगा।

दीपिका कक्कड़ की कैंसर से लड़ाई पर तेजस्वी प्रकाश ने कहा- 'मैं उनके लिए चिंतित हूं'

(एजेन्सी)।

रियलिटी शो सेलेब्रिटी मास्टरशेफ में अपने कार्यकाल के दौरान तेजस्वी प्रकाश और दीपिका कक्कड़ के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए थे। हालांकि, दीपिका को हाथ की चोट के कारण शो से बाहर होना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा छोटी हो गई। हाल ही में एक दिल दहला देने वाली खबर में, दीपिका ने खुलासा किया कि उन्हें स्टेज 2 लिवर कैंसर है।

इस खबर ने सोशल मीडिया पर प्यार, प्रार्थनाओं और समर्थन की जबरदस्त लहर पैदा कर दी। समर्थन की आवाजों में तेजस्वी प्रकाश भी शामिल हुईं, जिन्होंने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान दीपिका की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बात की। तेजस्वी ने साझा किया कि उन्होंने दीपिका के निदान के बारे में सुनने के बाद व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया था और उनके बीच हुई भावनात्मक बातचीत को याद किया।

बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल के भाई और अभिनेता सनी कौशल, जो शिद्दत में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में रैप इंडस्ट्री में प्रवेश किया है। वे अपने हाल ही में रिलीज हुए रैप गीत, मिड एयर फ्रीवर्स के लिए सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, जिसे मास अपील के साथ साझेदारी में रिलीज किया गया था। सनी ने रैप गीत को लिखा और गाया है। उन्होंने अपने नवीनतम उद्यम पर भी विचार किया और अपनी उत्तेजना व्यक्त की।

जेटली को बताया था जा रहा हूं... 9 साल बाद विजय माल्या ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं भगोड़ा या चोर नहीं

(एजेन्सी)।

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने चार घंटे के वीडियो पॉडकास्ट में दावा किया कि उन्होंने 2012 में अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद और 2015 के बीच चार बार सेटलमेंट ऑफर दिए, जिन्हें बैंकों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 2013 के बाद से पहली बार पॉडकास्टर राज शमनी के साथ बातचीत में माल्या ने कहा कि मेरा हमेशा से सेटलमेंट करने का इरादा था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भुगतान नहीं करना चाहता। किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक और पूर्व मालिक ने यह भी कहा कि उन्होंने हैदराबाद में अपने प्रशिक्षण अकादमी में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वे 14,000 करोड़ रुपये चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

इस वर्ष फरवरी में माल्या ने अपने वकील के माध्यम से कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया था कि यद्यपि बैंकों का लगभग 6,200 करोड़ रुपये का बकाया पहले ही वसूल किया जा चुका है, लेकिन 14,000 करोड़ रुपये की वसूली के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले वर्ष दिसंबर में लोकसभा में बयान दिया था। माल्या ने कहा कि 17 बैंकों से 6,203 करोड़ का लोन लिया। बैंकों ने संपत्तियों से 14,131.6 करोड़ रुपए रिकवर किए, जो कर्ज से ढाई गुना है। माल्या पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और लोन फंड के डायवर्जन के आरोप हैं। किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रेवरीज (होल्डिंग्स) लिमिटेड सहित उनकी कुछ कंपनियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 और पूंजी बाजार नियामक द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप है।

माल्या ने दावा किया कि वह तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी (जो 2009-12 के बीच सेवारत थे) के पास गए और कहा कि उन्हें एयरलाइन्स का आकार छोटा करने की जरूरत है, जो उस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। मुखर्जी ने कथित तौर पर उनसे कहा कि वह जैसा है वैसा ही जारी रख सकते हैं और इस तरह से यह सब शुरू हुआ। एयरलाइन्स के पतन का कारण बनने वाली घटनाओं की श्रृंखला पर शमनी के सवाल का जवाब देते हुए माल्या ने कहा कि 15 से 16 सरकारी बैंकों का समूह ऋणदाताओं के संघ का हिस्सा था। उन्होंने कहा किंगफिशर एयरलाइंस ने कभी भी एसबीआई से कोई पैसा उधार नहीं लिया। यह सिर्फ रिकॉर्ड को सही करने के लिए है।

एक देश, एक चुनाव-समय की आवश्यकता: अशोक शर्मा

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। ब्राह्मण खाप के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने आज एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए देश में "एक देश, एक चुनाव" की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में बार-बार चुनाव होने से न केवल आर्थिक संसाधनों की भारी बबार्दी होती है, बल्कि विकास कार्यों में भी गंभीर अवरोध उत्पन्न होते हैं।

अशोक शर्मा ने कहा कि हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे लगातार आचार संहिता लागू होती रहती है, जिससे सभी विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। न केवल सरकारें रुकती हैं, बल्कि समाज में भी अस्थिरता फैलती है। कभी पंचायत, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा यह सिलसिला थमना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनावों के कारण प्रशासनिक तंत्र चुनावी तैयारियों में उलझा रहता है, जिससे आम जनता के कार्य प्रभावित होते हैं। सबसे अधिक असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि चुनावों के दौरान विद्यालयों को मतदान केंद्र बना दिया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। शर्मा ने आगे कहा कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव हों, तो यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कम

खचीर्ली और कुशल होगी। इससे शासन में स्थिरता आएगी और लंबे समय तक विकास कार्य बिना बाधा के चल सकेंगे। यह केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा है।

उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और राज्यों के साथ व्यापक संवाद कर एक देश, एक चुनाव नीति को जल्द से जल्द लागू करे। ब्राह्मण खाप इस विषय पर समाज में जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न जनसभाओं, संगोष्ठियों और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रही है।

निगमायुक्त ने कर्ण कैनाल नाला व ड्रेन नम्बर 1 का निरीक्षण कर देखी साफ-सफाई

मानसून के दौरान जल भराव न हो, 15 जून से पहले मुकम्मल हो सफाई कार्य

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। मानसून के दौरान जल भराव न हो, इसके लिए नगर निगम गम्भीर है। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों को साथ लेकर कर्ण कैनाल नाला तथा ड्रेन नम्बर 1 का निरीक्षण कर किए जा रहे सफाई कार्यों को देखा। इस दौरान कार्यकारी अभियंता प्रियंका सैनी, सलाहकार महीपाल सिंह, सहायक अभियंता मदन मोहन गर्ग तथा सम्बंधित अभियंता मौजूद रहे।

दौरे में सर्वप्रथम निगमायुक्त ने एन.एन.-44 से शुरू होकर आर्वधन नहर को जाने वाली ड्रेन नम्बर 1 का निरीक्षण किया। उन्होंने एन.एच.-44 से सेक्टर 4-5 व हैरीटेज लॉन पुलिया पर जाकर ड्रेन की साफ-सफाई चेक की और अपनी संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए कि 15 जून से पहले-पहले ड्रेन की मुकम्मल सफाई करवाना सुनिश्चित की जाए।

बता दें कि सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेन नम्बर 1 की लाईनिंग कर ड्रेन की दोनो साईडों को पक्का किया जा रहा है। निगमायुक्त ने सिंचाई विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि जितना कार्य होता जाए, मिटद्टी को साथ-साथ उठवाते रहें। कर्ण कैनाल नाला की सफाई

पूरी-उन्होंने कर्ण कैनाल नाला के तीनो फेज पर जाकर नाला की सफाई देखी। बता दें कि नाला की सफाई मुकम्मल हो चुकी है, जिसे निगमायुक्त ने चेक किया। इसे लेकर उन्होंने मेला राम स्कूल से अस्थाई सब्जी मंडी पुलिया तक फेज 1, सब्जी मंडी से पुराना मेरठ रोड पुलिया तक फेज-2 तथा मेरठ रोड पुलिया से एन.एच.-44 तक फेज 3, का निरीक्षण कर सफाई देखी। उन्होंने कहा कि ड्रेन की नियमित तौर पर सफाई करवाते रहे, ताकि मानसून के दौरान वर्षा जल की निकासी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। मेला राम स्कूल से पहले वाले हिस्से की सफाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा करवाई जा रही है।

उन्होंने निगम अभियंताओं को निर्देश दिए कि बड़े नालों, रेन वाटर हार्वेस्टर तथा तालाबों का सफाई कार्य भी 15 जून से पहले करवा लिया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में जितनी भी जल भराव की संभावित जगह हैं, ऐसी सभी जगहों पर मानसून आने से पहले अपने इंतजाम पूरे कर लें, ताकि वहां पर पानी निकासी करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी डिस्पोजल पम्प स्थलों की भी सफाई करवाई जाए। डिस्पोजल पम्प पर मौजूद सभी मोटरें चालू हालत में रहनी चाहिए। सभी मोटरों की टैस्टिंग कर ली जाए।

कर्ण कैनाल रोड का किया निरीक्षण- इसके पश्चात निगमायुक्त ने कर्ण कैनाल रोड का निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति के साथ-साथ गुणवत्ता जांची। उन्होंने अभियंताओं के साथ पैदल चलकर सडक का निरीक्षण किया। कार्यकारी अभियंता प्रियंका सैनी ने निगमायुक्त ने बताया कि आधी सडक का निर्माण हो चुका है। सडक पर आने वाले रास्तों पर बैरीकेडिंग करवाई गई है, ताकि सडक निर्माण के दौरान वाहन न आए। निगमायुक्त ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि सडक का कार्य 30 जून तक पूरा करें, जिससे कर्ण कॉमर्शिलय कॉम्पलैक्स के दुकानदारों तथा यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कार्यकारी अभियंता तथा सलाहकार को निर्देश दिए कि सडक निर्माण का रेंडमली दौरा कर गुणवत्ता जांचते रहें।

उन्होंने कनिष्ठ अभियंता को निर्देश दिए कि सडक का रोजाना निरीक्षण करें। उन्होंने स्पष्टद्व किया कि सडक की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

पौधारोपण प्राकृतिक संतुलन के लिए जरूरी: मुकेश

एसबी ब्यूरो

बरौनी/बेगूसराय। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बरौनी प्रखंड क्षेत्र के सिमरिया एक, पपरौर, केशावे, महना, मैदा, निंगा, सिमरिया दो सहित विभिन्न पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया।

उक्त मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी मुकेश ने जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों से कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। इस दौरान प्रखंड क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम पदाधिकारी मुकेश ने कहा कि प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित

पर्यावरण देने के लिए पौधारोपण अनिवार्य है। मौके पर बीएफटी गौतम कुमार, लेखापाल पिंकी कुमारी, पंचायत तकनीकी सहायक सुभाष कुमार, कार्यपालक सहायक रोहित कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे।

134 नशा तस्कर गिरफ्तार; 1 किलो हेरोइन, 4.9 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। राज्य में नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर शुरू किए गए "युद्ध नशों विरुद्ध" के 97वें दिन पंजाब पुलिस ने आज 134 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1.08 किलो हेरोइन और 4.97 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है। इसके साथ ही सिर्फ 97 दिनों के भीतर गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 16,079 हो गई है। यह ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव के निदेर्शों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, **'संजना भारती'** को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संपर्क करें: दैनिक संजना भारती, समाचार पत्र नई दिल्ली

वाटसेप नम्बर: 9871221635

कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज रोड पर रेहडी-पटरी वालों को निगम ने डस्टबिन पेयर किए वितरित-डॉ. वैशाली शर्मा

'गीला व सूखा कचरा करें अलग-अलग, कचरा प्रबंधन में करें सहयोग'

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर निगम की सेनीटेशन टीम ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज रोड पर लगने वाली रेहड़ी-पटरी वालों को हरे व नीले रंग के डस्टबिन पेयर वितरित किए। यह कार्य अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार के नेतृत्व में किया गया।

निगमायुक्त ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कूड़े-कचरे के पृथक्करण पर नगर निगम जोर दे रहा है। रेहड़ी-पटरी वालों को कचरा अलग-अग करने के लिए हरे और नीले रंग के डस्टबिन वितरित किए गए हैं। यह कचरा प्रबंधन के लिए एक पहल है, ताकि गीला व सूखा कचरा अलग-अलग किया जा सके।

उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वाले अपने कचरे को इन डस्टबिन में डालकर कचरा पृथक्करण में नगर निगम की मदद कर सकते हैं। इससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में मदद मिलेगी और कचरा प्रबंधन में सुधार होगा। उन्होंने रेहड़ी-पटरी वालों से अपील करते कहा कि वह अपने कूड़े-कचरे को इधर-उधर न गिराकर इन डस्टबिन में ही डालें। वह गीला कचरे के लिए हरे तथा सूखे कचरे के लिए नीले रंग के डस्टबिन का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि कचरे को नगर निगम के कूड़ा एकत्र करने वाले वाहन में ही अलग-अलग करके डालें। उन्होंने बताया कि निगम अधिकारियों द्वारा रेहड़ी-पटरी वालों को चेताया भी गया है कि अगर वह अपने आस-पास गंदगी फैलाते हैं तो उनका चालान किया जाएगा।

इस मौके पर सफाई निरीक्षक मनदीप सिंह व संदीप कुमार, ट्रीगर मास्टर गुरदेव सिंह तथा लिपिक अंकित सैनी मौजूद रहे।

विधायक ने तरावड़ी में 42 लाख रुपये के सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास

पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने तरावड़ी के वार्ड नंबर 6, दया नगर में महर्षि वाल्मीकि मंदिर के नजदीक लगभग 42 लाख रुपये की लागत से बनने वाले एक आधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह भवन क्षेत्र के निवासियों के लिए सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों हेतु एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करेगा।

विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और कोई भी विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। इसी कड़ी में बनने वाला यह सामुदायिक भवन स्थानीय निवासियों को विवाह समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, सामुदायिक बैठकों और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक सुविधाजनक और सुसज्जित स्थान उपलब्ध कराएगा। ऐसे सामुदायिक केंद्र समाज के ताने-बाने को मजबूत करते हैं और लोगों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करते हैं।

शिलान्यास समारोह के दौरान, विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली के महत्व का संदेश दिया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को हरियाली बढ़ाने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ पर्यावरण ही एक स्वस्थ समाज की नींव है।

इस मौके पर नगरपालिका सचिव अजीत, मंडल अध्यक्ष शिवम बंसल, देवेन्द्र कामरा, राजीव नारंग, वीरेंद्र बंसल, शिशपाल गुप्ता, देसराज पार्षद, मल्होत्रा जी, संजय,संयोगिता गुप्ता, प्रवीन गुप्ता, नरेश गाबा, लखविंद्र, नीतू,पंकज, नवदीप, जतिन, कमल, प्रदीप, रामकुमार गुप्ता, प्रेम, रणजीत भारद्वाज व अन्य वार्ड के साथी उपस्थित रहे।

कौंधियारा पुलिस ने लापता युवक को सकुशल किया बरामद

संजना भारती संवाददाता

मनोज कुमार बिन्द

कौंधियारा। थानाक्षेत्र के बहापार गाँव का रहने वाला एक युवक 4 जून को लापता हो गया था। घर वालों ने युवक की काफी खोजबीन की लेकिन युवक का कहीं पता नहीं चला। वहीं परिजनों ने कौंधियारा पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की थी। कौंधियारा थानाक्षेत्र के ग्रामसभा नौगवां बहापार निवासी राकेश पटेल उर्फ राहुल 25 पुत्र रामचंद्र पटेल 4 जून दिन मंगलवार रात 10:30 बजे संदिग्ध परिस्थित में लापता हो गया था। घर वालों ने गुरुवार को कौंधियारा थाने पर लिखित तहरीर देकर गुमशुदा युवक की तलाश करने की बात कहीं थी।

परिजनों के तहरीर के आधार पर थानाप्रभारी कुलदीप शर्मा ने गुमशुदा युवक के तलाश के लिये पुलिस टीम गठित कर-के युवक की तलाश शुरू कर दी। उपनिरीक्षक अभय यादव ने 6 जून को पुलिस टीम के साथ सड़वा नहर पुलिया के पास से गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद करते हुये परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस कार्यशैली में योग का समावेश होना अति आवश्यक: डॉ अरशिन्दर सिंह चावला

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक डॉ. अरशिन्दर सिंह चावला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य देश-विदेश के लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए कुशल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आप सभी जानते हैं कि योग भारत की प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। योग ने विश्व में न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि विश्व गुरू बनने के मार्ग को भी प्रशस्त किया है। विश्व स्तर पर योग को स्वीकार किया जाना हम सबके लिए गौरवशाली है।

निदेशक डॉ. अरशिन्दर सिंह चावला शुक्रवार को मधुबन पुलिस अकादमी के वच्छेर स्टेडियम में 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हरियाणा, योग आयोग एवं पतंजलि के तत्वावधान में हरियाणा पुलिस अकादमी के सहयोग से विशाल योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया था, 11 दिसम्बर 2014 को भारत के इस प्रस्ताव को 177 देशों के समर्थन के साथ स्वीकार कर लिया गया और 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस क्रम में 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत बडे स्तर पर मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन पद्धति है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि योग वह औषधि है जो ब्रह्मांड में किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति रखती है। नियमित योग अभ्यास से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है जो आपको सकरात्मकता की और अग्रसर करता है जो व्यक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस कार्यक्रम में योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया गया। इस योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 हजार प्रशिक्षणार्थियों, स्टॉफ स्दस्यों व अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने योग के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए सामान्य प्रोटोकॉल निर्धारित है, इस प्रोटोकॉल में सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम व ध्यान की क्रियाओं का समावेश किया गया है। हर आयु वर्ग के व्यक्ति इस आसान क्रियाओं को कुछ सावधानियों के साथ आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस की ओर संकेत करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि पुलिस जीवन चुनौतियों से भरा है, इसलिए आपकी कार्यशैली में योग का समावेश होना अति आवश्यक है। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया।

इस अवसर पर योग आयोग विभाग हरियाणा के वाइस चेयरमैन रोशन लाल ने कहा कि इस वर्ष हरियाणा का संकल्प है-रोग मुक्त हरियाणा-नशा मुक्त हरियाणा।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दूनी समर कैंप में हुए विभिन्न कार्यक्रम

संजना भारती संवाददाता

दूनी/टोंक। उपखंड के दूनी तहसील मुख्यालय स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की के तत्वाधान में चल रहे हैं कौशल विकास एवं अभिरुचि शिविर समर कैंप में आज पर्यावरण दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया।

कार्यक्रम संयोजक अशोक शर्मा ने बताया कि शिविर के मॉर्निंग सेशन में पीएम श्री प्रभारी सुरेन्द्र सिंह नरूका ने बालकों के साथ पर्यावरण के घटक जल, हवा, मिट्टी, वन, संरक्षण के साथ प्राचीन जलाशयों की स्वच्छता पर विस्तार से चर्चा की गई तथा

वृक्ष मित्र और वृक्ष संरक्षक बनने को प्रेरित किया। इसके पश्चात वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक शिवजी लाल चौधरी के निर्देशन में खेल मैदान में 5 जून 5 वृक्ष थीम पर पांच नीम के पेड़ लगाए गए साथ ही छात्रों सहित दक्ष प्रशिक्षको ने वर्षा ऋतु में न्यूनतम पांच पांच वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। इसके पश्चात एनएसएस प्रभारी गिरधारी लाल शर्मा के साथ बालकों ने खेल मैदान एवं विद्यालय परिसर की सफाई की। व्यवस्थापक महावीर प्रसाद बडगूजर एवं लादू लाल मीणा के नेतृत्व में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। दौड़ में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को मोमेंटो देकर पुरस्कार किया गया।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्ष प्रशिक्षक मुकेश गुर्जर, रेखा मीणा, संगीता जैन, श्वेता माथुर, सूर्य प्रताप सिंह नाथावत आदि उपस्थित रहे।

शंकरपुर पंचायत में कृषि जन कल्याण चौपाल का आयोजन

संजना भारती संवाददाता

भरगामा (अररिया)। भरगामा प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर पंचायत में शुक्रवार को कृषि जनकल्याण चौपाल कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। शंकरपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया उमेश कुमार यादव ने किया।

इस अवसर पर कृषि सलाहकार संतोष कुमार सहित कई कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ, जैविक खेती को अपनाने की प्रक्रिया व खरीफ मौसम में धान की बुवाई एवं रोपनी की वैज्ञानिक विधियों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। किसानों को अच्छे किस्म के धान बीज की पहचान, मिट्टी की जांच और संतुलित उर्वरक उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि अनुदान योजनाओं, बीज वितरण, फार्मर रजिस्ट्रेशन तथा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की जानकारी दी। किसानों को बताया गया कि कैसे वे ऑनलाइन माध्यम से अनुदान व सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कृषक पंजीकरण और कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से कृषि से जुड़ी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में सरकार की पहल पर भी प्रकाश डाला गया। चौपाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। उपस्थित किसानों ने खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए और तकनीकी सवाल पूछे जिनका विशेषज्ञों ने समाधान प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम के मौके पर किसान सुरेन्द्र मिश्रा, श्यामानंद सिंह, श्रीनारयण ऊर्फ लाल सिंह, सरोज सिंह, पिंटू सिंह, नरेश यादव सहित कई अन्य कृषक प्रतिनिधि मौजूद थे।

बेटी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर 43 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया

संजना भारती संवाददाता

बदायूं। 5 जून को समाजसेवी लवकेश गुप्ता द्वारा अपनी बेटी मीशिका गुप्ता व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था।

रक्तदान सिविल का उद्घाटन सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक रजनीश उपाध्याय द्वारा किया गया। इस रक्तदान शिविर में लवकेश गुप्ता सहित उनके 43 समाजसेवियों साथियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान किया गया। इस रक्तदान शिवर में शहर की प्रतिष्ठित सराफा व्यापारी रोशन लाल एंड संस के मालिक अमित वर्मा ने इस रक्तदान शिविर मे 52 बार रक्तदान कर समाज में एक अंगूठी मिशाल पेश की। अमित वर्मा ने बताया किरक्तदान करने से हमारा शरीर पहले से स्वस्थ और

ऊजार्वान बनता है। वक्त करने के 24 घंटे के अंदर हमारे शरीर में उतना ही रक्त दोबारा बन जाता है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति तीन माह के बाद रक्तदान कर सकता है रक्तदान से किसी का जीवन बच सकता है। लवकेश गुप्ता ने बताया यह रक्तदान शिविर बेटी के जन्मदिन के अवसर पर पिछले 4 वर्षों से लगातार लगाया जा रहा है और भविष्य में भी लगता रहेगा। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से जरूर मंद लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ने उन्हें रक्त दिया जाता है और उसके जीवन को बचाया जाता है आपका एक रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता किसी के घर परिवार में खुशहाली ला सकता है रक्तदान महादान।

विधानसभा अध्यक्ष ने 8 करोड़ 11 लाख की 2 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन

4 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से नगला मेघा चौक से घरौंडा तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का किया शिलान्यास

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने शुक्रवार को घरौंडा विधानसभा के लिए बड़ी सौगात देते हुए 8 करोड़ 11 लाख 13 हजार रुपये की लागत से दो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। उन्होंने सर्वप्रथम मिर्गाहिन गांव में 3 करोड़ 45 लाख 13 हजार रुपये की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का उद्घाटन किया। इसके उपरांत 4 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से नगला मेघा चौक से घरौंडा तक सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण सर्वप्रथम मिर्गाहन गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने 3 करोड़ 45 लाख 13 हजार रुपये की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का पगड़ी पहनाकर व पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। उन्होंने वहां मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा 0.71 एकड़ में बनाई गई इस पीएचसी का निर्माण कार्य एक जुलाई 2019 को शुरू किया गया। इसके भूतल का क्षेत्र 9175 वर्गफुट और प्रथम तल (ममटी) का 717 वर्गफुट है।

इस पीएचसी से आसपास के 20 गांवों की 40,000 आबादी को फायदा

होगा। सीएचसी कुंजपुरा के तहत आने वाली इस पीएचसी में नर्सिंग स्टेशन, पुरुष, महिला व बेबी वार्ड, दंत चिकित्सा व आयुष चिकित्सा कक्ष, आयुष पैरामेडिकल स्टाफ रूम, एक्स-रे रूम ऑपरेशन थिएटर, चिकित्सक कक्ष, नसबंदी कक्ष, प्रतीक्षा गृह, पंजीकरण कक्ष प्रवेश हाल, रैंप और सेंट्रल कोर्ट यार्ड, स्टोर प्रयोगशाला औषधालय कक्ष, तथा पुरुष व महिला टॉयलेट बनाया गया है। पीएचसी के तहत 6 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि इस पीएचसी के बनने से आसपास के गांवों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां डाक्टरों सहित पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया गया है। कहीं कोई कमी नोटिस में आई तो उसे भी दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली पारी में कोरोनाकाल में आई अड़चनों के बावजूद हलके में अनेक विकास कार्य कराए गए। पिछले 10 सालों में कई सड़कें, पुल, अस्पताल, आईटीआई, घरोंडा में बस अड्डा, सब-डिवीजन के साथ-साथ करनाल में नई चीनी मिल और मेरठ रोड को नेशनल हाईवे बनवाया गया। हलके में रिंग रोड और एनसीसी अकेडमी का निर्माण जारी है।

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण मेरठ रोड पर स्थित नगला चौक पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने नगला मेघा चौक से घरौंडा तक बनाई जाने वाली 18. 540 किलोमीटर लंबी सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 4 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत आएगी। कार्य तीन महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में सुधार और विकास के प्रति सरकार गंभीर है। पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, यह सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कोरोनाकाल में भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले बेहतर रही। श्री कल्याण ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में एक -दूसरे का सहयोग करने से हर समस्या का समाधान संभव है। आने वाले समय में हलके को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मिली नई जिम्मेदारी के बावजूद वे हलका वासियों को पूरा समय देते रहेंगे। लोगों से कहा कि वे निसंकोच विकास संबंधी मांगें रखें।

इस मौके पर पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन राजकुमार, संदीप सिंह, जेई ईशम सिंह व मोहन सिंह, सीएमओ डा. पूनम चौधरी, एसएमओ डा. संदीप अबरोल, एमओ डॉ राहुल डॉ माला, डिप्टी सीईओ जिला परिषद रोजी रोज, पूर्व मंडल अध्यक्ष जोगिंदर राणा, मंडल अध्यक्ष सचिन राणा, महामंत्री राजेश लाठर, विक्रम पाल, नगला फॉर्म के सरपंच सुधीर, भाजपा नेता धीरज खरकाली आदि मौजूद रहे।

डीसी ने किया कैथल ब्लॉक की ड्रेनों में सफाई कार्य का निरीक्षण

बारिश के पानी की समुचित निकासी के लिए समय रहते ड्रेनों की सफाई जरूरी

संजना भारती संवाददाता

कैथल। डीसी कैथल प्रीति ने शुक्रवार दोपहर बाद कैथल ब्लॉक की ड्रेनों में करवाए जा रहे साफ-सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए और कहा कि ड्रेनों की सफाई कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी समय रहते ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित करवाएं। ताकि बारिश के पानी की बिना किसी बाधा के निकासी हो सके। उन्होंने ड्रेनों में मुख्य चौक-चौराहों के साथ-साथ कई किलोमीटर तक ड्रेनों की पटरियों से जहां तक संभव हुआ वाहनों की मदद से और उसके बाद पैदल जाकर भी बारीकी से डेनों की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया।

डीसी ने ड्रेनों में मनरेगा से करवाए जा रहे सफाई के कार्य, पोकलेन व जेसीबी से करवाए जा रहे कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि ड्रेनों के अंदर से जहां तक संभव हो सके गाद निकाली जाए। साथ ही ड्रेनों में उगी हुई जलखूंबी की सफाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा किनारों पर जो पेड़ खड़े हैं, उनकी कटाई-छंटाई जरूरी है। क्योंकि पानी की निकासी के समय ये टहनियां पानी के बहाव में रुकावट पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि जो गाद निकाली जाए, उसका उठान भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसा न हो कि जो गाद निकाली जाए, वह फिर से बहकर ड्रेनों में चली जाए। डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समय रहते ड्रेनों, नालों की सफाई की जाए। ताकि बारिश के समय में लोगों को जलभराव जैसी स्थितियों का सामना न करना पड़े। इन्हीं निर्देशों मद्देनजर अधिकारी सफाई कार्य में गंभीरता दिखाएं। डीसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कहीं कार्य में लापरवाही मिलती है तो कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डीसी ने कहा कि बारिश के दौरान ड्रेनों से पानी की निकासी अच्छे से हो, इसके लिए निरीक्षण किया गया है। बैठकों में निर्देश के बाद फील्ड में औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कई जगह कार्य में गति थोड़ी धीमी है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि काम में तेजी लाई जाए। चाहे मैन पावर बढ़ानी पड़े या फिर मशीनें लगानी पड़ें। कई जगह शत-प्रतिशत सफाई का कार्य मिला है। जहां थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से सुधार कार्य का भी निरीक्षण किया जाएगा।

इस अवसर पर डीएमसी सुशील कुमार, एसडीएम अजय सिंह, डीआरओ चंद्रमोहन, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता व अन्य अधिकारियों के अलावा जन स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।

जिला कैथल के गांव कैलरम व जाखौली लिंगानुपात सुधार में अव्वल

तीन-तीन टॉपर्स बेटियों को नकद पुरस्कार देकर किया सम्मानित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। कैथल जिले के कैलरम व खंड राजौंद के गांव जाखौली को लिंगानुपात सुधारने पर जिला के सर्वश्रेष्ठ गांव रूप में चुना गया है। वर्ष 2023 में कैलरम गांव में 45 लड़कों के मुकाबले 70 लड़कियों ने जन्म लिया था। यानी एक हजार लड़कों की दर के मुकाबले 1556 बेटियां जन्मीं हैं। वहीं जाखौली गांव में वर्ष 2024 में 44 लड़कों के मुकाबले 68 लड़कियों ने जन्म लिया था। यहां का लिंगानुपात 1545 रहा था। इसी कारण पीएनडीटी एक्ट के तहत बेस्ट विलेज अवार्ड योजना में दोनों गांव की 10वीं में टॉपर रहने वाली तीन-तीन बेटियों को शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से डीसी प्रीति ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं दोनो गांवों की पंचायत, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, ग्राम पंचायत सहित स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर प्रोत्साहित किया।

डीसी प्रीति ने बताया कि पीएनडीटी एक्ट के तहत जिले में लिंगानुपात में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते गांव कैलरम व जाखौली के लिंगानुपात में काफी सुधार आया है। जिस कारण पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार की बेस्ट विलेज अवार्ड स्कीम के तहत दोनों गांवों में दसवीं में पिछले दो साल में प्रथम रही तीन-तीन बेटियों को नकद ईनाम के लिए चुना गया है। इनमें कैलरम गांव की मुस्कान, काजल व मधु को कक्षा 10वीं में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने पर 75 हजार, 45 हजार व 30 हजार रुपये का चैक देकर सम्मानित किया। इसी प्रकार जाखौली गांव की 10वीं कक्षा में प्रथम रहने वाली छात्रा मधु को 75 हजार, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली आरती को 45 हजार व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली तन्नु को 30 हजार रुपये का चैक देकर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर कैलरम की गांव की सरपंच सीता देवी व जाखौली गांव की सरपंच ऊषा देवी सहित आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर व स्वास्थ्य कर्मियों को अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि आगे भी अपने गांव का लिंगानुपात में सुधार को बरकरार रखने के लिए प्रयास करते रहें। उन्होंने सभी जिला वासियों से आह्वान किया वे कैलरम व जाखौली गांव से प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वे शिक्षा, खेल, विज्ञान के क्षेत्र में खूब देश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटियों के साथ साथ पुत्रवधुओं का भी सम्मान करें, उन्हें बहु नहीं बल्कि अपनी बेटी समझें। सास-बहु मिलजुल कर रहें।

कैलरम की गांव की सरपंच सीता देवी ने बताया कि लिंगानुपात को लेकर गांव में जागरूकता अभियान चलवाती हैं। लड़का हो या लड़की दोनों के जन्म पर जन्म देने वाली मां को दो किलो देसी घी दिया जाता है। इसी प्रकार से जाखौली की सरपंच ऊषा देवी ने भी पंचायत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। सिविल सर्जन डा. रेणु चावला ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ मुहिम को बढ़ावा देने के प्रयासों में जिला के गांवों की जनवरी से दिसंबर तक के लिंगानुपात की जानकारी जुटाई जाती है। योजना के तहत लिंगानुपात में अव्वल रहने वाले गांव की कक्षा 10वीं में टॉपर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस अवसर पर पीएनडीटी इंचार्ज डा. गौरव पूनिया, राजेश कुमार, डा. संदीप सिंह राजौंद, डा. बृज मोहन सहित संबंधित गांव की आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स मौजूद रहीं।

निर्मम घटना के विरोध में इनेलो पार्टी 10 जून को करेगी प्रदर्शन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। इनेलो के किसान सैल प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा ने कहा कि पानीपत के गाँव निजामपुर के निवासी किसान की बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी बाउंसरों द्वारा जलाकर हत्या कर दी गई है। जिसकी कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि इस निर्मम घटना के विरोध में इनेलो पार्टी हर ज़िला मुख्यालय पर 10 जून समय दस बजे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा की देखरेख में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था का दिवाला पिट गया है। हर रोज प्रदेश में बलात्कार, कत्ल और फिरौती की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी प्रदर्शन में उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देगी और सरकार को इस लिए सभी ज़िला और हल्का प्रधानों से अनुरोध किया है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों को सूचित करें। इसके अलावा पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी सूचित करते हुए सभी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों और जिला संयोजकों को भी प्रदर्शन में शामिल होने के साथ सक्रिय रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अनुरोध करें। इसलिए आपसे अनुरोध है की गाँव-गांव जाकर कार्यकताओं से संपर्क करें और प्रदर्शन को सफल बनाने का पर्यास करें।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को कुरुक्षेत्र का ब्रह्मसरोवर होगा योगमय

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 21 जून 2025 को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को सुव्यस्थित व अनूठे ढंग से मनाने का निर्णय लिया है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव भी पधारेंगे। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर केवल योग प्रदर्शन ही नहीं होगा बल्कि लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया जाएगा। यह सरकार के स्वस्थ, जागरूक और पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि लोगों में अंतरराष्ट्री? योग दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब तक 70 हजार से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में फफड़ाना में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असन्ध। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में असंध खंड के गांव फफड़ाना में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में त्रिवेणी लगाई गई। इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन की बी आर सी रानी मलिक ने बताया कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हमें जल एवं पेड़ पौधों के बारे में संवेदनशील रहना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है पर आधारित है।

इस मौके पर एस सी पी ओ बलविंदर सिंह, ग्राम सचिव अजमेर, ग्राम सचिव अंकित सिंह, सरपंच सीमा देवी व ग्रामवासी मोहित, रिंकू आदि मौजूद रहे।

आरोही स्कूल सोंगरी में भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन

शिविरार्थियों उत्साह पूर्वक समर कैंप में ले रहे हैं हिस्सा: प्रिंसिपल

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। शिक्षा विभाग हरियाणा के आदेशानुसार सभी सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भारतीय भाषा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल प्रिंसिपल सुनीता आहूजा ने बताया कि आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोंगरी में भी इस शिविर में शिविरार्थियों में आत्म-परिचय, शब्दावली निर्माण, वास्तविक जीवन में बातचीत के अभ्यास, संस्कृति की सराहना, सुदृढ़ीकरण और आत्मविश्वास निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भाषा सीखने को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता पर जोर देती है और भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय एकता के लिए महान उपकरण के रूप में देखती है।

छोटी उम्र में विद्यार्थी तेजी से भाषा सीखने में सक्षम होते हैं और संचार कौशल में जल्दी सुविधा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इस कैंप के दौरान बच्चों को पहले दिन सामान्य अभिवादन, विभिन्न स्थान पर होने वाला व्यवहार व तोर तरीकों के बारे में अवगत कराया गया।

दूसरे दिन उन्हें वास्तविक जीवन के विभिन्न व्यवसायों का अभ्यास व सार्वजनिक स्थानों पर सभ्य व्यवहार के बारें में बताया गया। तीसरे दिन छात्रों को देशभक्ति संगीत व कला के माध्यम से देश की संस्कृति से अवगत कराया गया। चौथे दिन छात्रों को विभिन्न प्रकार के मसाले, फल सब्जियों व उनके पोषण के महत्व के बारे में बताया गया। छात्रों को बिना गैस जलाए स्नैक्स आइटम भी बनाने सिखाए गए जिसमें छात्रों ने भेलपुरी, सैंडविच, नींबू पानी व फ्रूट, सलाद का आनंद लिया। विद्यालय में विश्व पर्यावरण के दिवस पर भी छात्रों से पौधारोपण करवाया गया।

शिविरार्थियों को अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय प्राचार्य सुनीता अहूजा ने बताया कि शिविरार्थियों बहुत ही उत्साह पूर्वक इस समर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं व 8 जून को कैंप का समापन किया जाएगा।

नपा राजौंद ने सफाई कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार धाँदी के नेतृत्व में मेन बाजार में चलाया सफाई अभियान

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। नगर पालिका राजौंद ने मेन बाजार वार्ड नंबर 9 व 11 में सफाई कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार धाँदी की अगुवाई में विशेष सफाई अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व डीएमसी कैथल के निर्देश अनुसार व नपा सचिव नरेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

नपा सफाई कोर्डिनेटर प्रदीप कुमार धाँदी ने दुकानदारों व नागरिकों को सफाई का महत्व बताते हुए सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नपा राजौद का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है गीला व सूखा कचरा अलग-अलग डस्टबिन में इक्कठा कर डोर-टू-डोर वाहन के अलग-अलग बनाए गए निर्देशित भाग में डालें।

मार्केट यूनियन राजौंद "बाला जी सेवा समिति" प्रधान भीम सिंह राणा ने सफाई अभियान में भाग लिया। उन्होंने सफाई व्यवस्था बनाए रखने में दूकानदारों की ओर से सहयोग करने का श्वसन दिया। प्रधान ने राजौंद के सभी दुकानदारों से अनुरोध किया है कि कूड़ा-करकट, पुराने पोलिथीन, लिफाफे बाहर गली में न फेंकें। पोलिथीन नालियों को अवरूद्ध करते हैं। सरकार व प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। कपड़े या कागज के थैले का प्रयोग करें।

नागरिकों, दुकानदारों को सफाई रखने के लिए किया जा रहा है जागरूक: नपा सचिव नरेंद्र शर्मा

नपा सचिव ने क्या बताया

नपा सचिव नरेंद्र शर्मा ने भेजे संदेश में कहा कि हरियाणा सरकार, उपायुक्त कैथल, डीएमसी कैथल के निर्देश अनुसार राजौंद में सफाई पखवाड़ा मनाया जा रहा है। नागरिकों व दुकानदारों को सफाई का महत्व बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक सींगल यूज प्रतिबंधित पोलिथीन पन्नी का प्रयोग न करें। फल, सब्जी, कूड़ा-करकट पोलिथीन पन्नी में डाल कर नाले या गली में न फैंके। कूड़ा-करकट हमेशा डोर टू डोर के वाहन में डालें। सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नपा प्रशासन राजौंद का सहयोग करें।

शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के लिए करें अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण: महीपाल ढांडा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार

चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए और इसमें पाठ्यक्रम उपरांत विद्यार्थियों के इंटर्नशिप प्रशिक्षण को लेकर किसी प्रकार का समझौता न किया जाये।

शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जे.सी. बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए, फरीदाबाद में इंटर्नशिप अवसरों पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला को बतौर मुख्यातिथि संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन को हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद (एचएसएचईसी) द्वारा विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप अवसरों के लिए परस्पर सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष प्रो. एस.के. गखड़, जे.सी. बोस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुशील कुमार तोमर और संबद्ध कॉलेजों के निदेशक-प्राचार्य शामिल रहे।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से आह्वान किया कि वे विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम में बदलाव की पहल करें और कुलपति के स्थान पर भारतीय परम्परा के अनुसार कुलगुरु लिखना एवं उपयोग करना प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक संशोधन लाया जायेगा। विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम में बदलाव का प्रस्ताव भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से अखिल भारतीय महामंत्री श्री सुनील शर्मा द्वारा रखा गया था। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, ताकि हमारे विद्यार्थी वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके।

उन्होंने प्रसन्नता जताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि सभी शिक्षकों नीति को इसमें निहित भाव के साथ लागू करें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में छात्रों के लिए इंटर्नशिप को सरल तरीके से लाया जा रहा है, ताकि छात्र उद्योग के साथ-साथ अगर चाहे तो गांव में रह कर भी इंटर्नशिप कर सकें। इसके साथ ही, शिक्षकों का ध्यान रखना होगा कि कोई छात्र इंटर्नशिप का झूठा सर्टिफिकेट लेकर न आये।